

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II
(अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

26 दिसम्बर, 2020

ब्रिटेन ने नो डील ब्रेक्जिट की संभावना को टाल दिया, नहीं तो इसका विनाशकारी प्रभाव सभी पर पड़ता।

पोस्ट ब्रेक्जिट संक्रमण काल समाप्त होने के कुछ दिन पहले, यू.के. और यूरोपीय संघ ने गुरुवार को टैरिफ-फ्री ट्रेड समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 2016 में ब्रिटेन के संकीर्ण निर्णय (जहाँ ब्रिटेन ने सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स को छोड़ने की बात कही थी) के परिणामों को कुछ हद तक कम कर देगा। अंतिम समय में हुए इस समझौते ने विपत्ति पूर्ण “नो डील” परिदृश्य को टाल दिया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रिटेन अगर बिना किसी डील के यूरोपीय संघ से अलग होता तो इसका असर बहुत बुरा होता। इस पोस्ट-ब्रेक्जिट समझौते से कारोबार और उद्योग जगत के लिए कई अहम बदलाव होंगे जिनमें ब्रिटेन और ईयू के अलग बाजार प्रमुख होंगे। इस डील से ब्रिटेन के कारोबारी राहत की साँस लेंगे जो कोरोना महामारी के बाद सीमा पार व्यापार में मुश्किलों और आयात पर टैक्स से डरे हुए थे।

ईयू, ब्रिटेन का सबसे करीबी और सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि इस डील के दायरे में साल 2019 में हुआ 668 बिलियन पाउंड का व्यापार भी आता है। जब तक ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य था, ब्रिटेन की कम्पनियां ईयू की सीमा में कहीं भी बिना कोई टैक्स चुकाए अपने सामान बेच सकती थीं। अगर यह व्यापार समझौता न हो पाता तो कारोबारियों को ईयू में अपना सामान बेचने के लिए भारी टैक्स चुकाना पड़ता जिसका उनके बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ता।

इस समझौते के कारण यूरोपीय संघ में बने रहने की तुलना में, देश को अब सकल घरेलू उत्पाद का 4% का नुकसान उठाना पड़ सकता है और यदि समझौता नहीं होता तो सकल घरेलू उत्पाद का 6% का संभावित नुकसान होता। इसके अलावा, खाद्य उत्पादों के 75% आयात के लिए यूरोपीय संघ पर यू.के. की निर्भरता को देखते हुए, उपभोक्ताओं और खुदरा अर्थव्यवस्था के लिए शून्य शुल्क व्यापार का महत्व काफी अधिक है।

आम नागरिक के लिए ब्रेक्जिट का सबसे बड़ा असर संभवतः बेरोकटोक आवाजाही और काम करने के अधिकार पर प्रतिबंध है। यूरोप के एकल बाजार में टैरिफ-फ्री पहुंच की गारंटी के बदले में महसूस किया गया है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धा के नियमों और पर्यावरण नियमों को कम नहीं करेगा। वार्ता में अधिक विवादास्पद मुद्दों के बीच, यह व्यवस्था ‘सिंगापुर-ऑन-थेम्स’ विकास मॉडल से संभावित आर्थिक खतरे के बारे में आशंकाओं को व्यक्त करती है, जो यू.के. के बाहर यू.के. को परेशान कर सकती है।

सबसे बड़ी बाधा ब्लॉक ईयू की मत्स्यपालन के लिए ब्रिटिश समुद्र तक पहुंच थी, जिसे लंदन ब्रेक्जिट के बाद किसी भी हाल में पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। अब एक साढ़े पांच साल की संक्रमण अवधि है जो प्रभावित यूरोपीय संघ राज्यों के लिए निरंतर पहुंच की गारंटी देती है। उत्तरार्द्ध के लिए कम शर्तों से ब्रिटिश मत्स्य पालन में मदद की उम्मीद है। अब एक बड़ी चुनौती सीमा चेक और लाल फीताशाही को न्यूनतम रखना होगा, इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि आपूर्ति श्रृंखला बाधित न हो।

राजनीतिक रूप से, ब्रेक्जिट के बाद की साझेदारी ब्रिटिश समाज को ध्रुवीकृत करने वाले विद्वेष को समाप्त कर सकती है। प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने अनुमानित रूप से देश की संप्रभुता को बहाल करने का वादा किया है जो 47 साल की यूरोपीय संघ की सदस्यता के तहत खो गयी थी। उनकी कंजरवेटिव पार्टी का संसदीय बहुमत अगले हफ्ते की शुरुआत में स्वतः मंजूरी देने में सक्षम होगा।

विपक्षी लेबर पार्टी ने समझौते के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। गुरुवार की शर्तें अस्थायी रूप से 1 जनवरी से लागू होंगी, जबकि यूरोपीय संसद को कुछ ही हफ्तों में अपना समर्थन देने की उम्मीद है। निश्चित रूप से कंजरवेटिव पार्टी के लिए विजय का क्षण हो सकता है, लेकिन वे आपसी सहयोग के क्षेत्रों में यूरोपीय संघ के 27 देशों से मुकाबले कर रहे अपने देश की वास्तविकता को नकार नहीं सकते हैं। यह राष्ट्रीय संप्रभुता की सीमा तय करेगा।

ब्रेक्जिट और भारत पर इसका प्रभाव

चर्चा में क्यों?

- महीनों लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर सहमति बन गई है।
- अब इसके बाद ब्रिटेन अब यूरोप के एकल बाजार का हिस्सा नहीं रहेगा।
- इस समझौते को पोस्ट ब्रेक्जिट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम दिया गया है।
- विदित हो कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से 31 जनवरी, 2020 को ही बाहर हो गया था, लेकिन इसके बाद वह यूरोपीय संघ के नियमों का पालन कर फिलहाल 31 दिसंबर तक नए आर्थिक रिश्ते के संक्रमण काल में है।
- अब दोनों पक्ष एक-दूसरे के क्षेत्र में जाकर अपना माल बेच सकेंगे और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा।

ब्रेक्जिट से भारत को फायदा या नुकसान?

- ब्रेक्जिट ट्रेड डील के बाद ब्रिटेन के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता हो सकता है।
- इससे भारत-ब्रिटेन के बीच कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- ब्रिटेन एक छोटा देश है, लेकिन वह एक सेंट्रल मार्केट है।
- पुर्तगाल और ग्रीस जैसे कई देश ब्रिटेन से सामान ले जाते हैं।
- ब्रिटेन के साथ एफटीए होने से भारत को एक विशाल बाजार मिल सकता है।

इन क्षेत्रों में भारत को मिलेगा मौका

- यूरोपीय संघ के साथ भी भारत एफटीए की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ।
- ब्रिटेन के ईयू से अलग होने से भारत को लाभ होगा।
- बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन दोनों ही ब्रेक्जिट की प्रक्रिया में घाटे में रह सकते हैं।

- यहां भारत प्रोडक्ट और सेवा ऑफर करने के मामले में अहम भूमिका निभा सकता है।
- भारत टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, डिफेंस और फाइनेंस में बड़ा भागीदार बन सकता है।

क्या है ब्रेक्जिट?

- ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन+एक्जिट। ब्रेक्जिट का सीधा सा मतलब है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना।
- इसकी शुरुआत साल 2008 में हुई जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई थी।
- ब्रिटेन ने साल भर पहले ही यूरोपीय यूनियन से बाहर जाने का ऐलान कर दिया था।
- देश में महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, जिसका समाधान निकालने और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के प्रयास चल रहे थे।
- साल 2016 में ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन से एक्जिट होने को लेकर जनमत संग्रह हुआ था।
- 27 मार्च, 2017 को ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की।
- यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने की समयसीमा को पहली बार 29 मार्च, 2019 से बढ़ाकर 12 अप्रैल, 2019 किया गया।
- उसके बाद इस समयसीमा को 31 अक्टूबर 2019 और फिर 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ाया गया।
- कैसे बना यूरोपीय यूनियन
- द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध में भाग लेने वाले सभी देशों को नुकसान झेलना पड़ा था।
- इस युद्ध के खत्म होने के पांच साल बाद फ्रांस और जर्मनी ने एक संधि की थी, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अब कोई युद्ध नहीं करेंगे।

- इस योजना के तहत छह देशों ने साल 1950 में एक डील पर हस्ताक्षर किए।
- सात साल बाद रोम में एक संधि हुई। जिसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईसीसी) का गठन किया गया।
- इसी यूरोपीय आर्थिक समुदाय को आज यूरोपीय यूनियन के रूप में जाना जाता है।
- वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल हैं। जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस,

चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, रिपब्लिक ऑफ ऑयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं।

- साल 1973 की शुरुआत में तीन नए देश इससे जुड़े। इनमें से एक देश ब्रिटेन था। ब्रिटेन के अलग होने के बाद वर्तमान में ईयू में 27 सदस्य हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

- प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-
1. ब्रिटेन ईयू से बाहर निकलने वाला दूसरा देश है और इसे ही ब्रेक्जिट (ब्रिटेन का एक्जिट) के नाम से जाना जाता है।
 2. ब्रेक्जिट का फैसला वर्ष 2016 में जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था।
 3. पोस्ट ब्रेक्जिट डील के बाद अब ब्रिटेन और ईयू सीमा पार होने वाले व्यापार पर केवल 3% टैक्स (टैरिफ) लगाए जाएंगे।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- (a) केवल 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) केवल 3

Expected Questions (Prelims Exams)

- Q. Consider the following statements:-
1. Britain is the second country to exit from EU and it is known as Brexit.
 2. Brexit was decided on the basis of referendum in 2016.
 3. After Post-Brexit deal, now only 3% tax (tariff) will be levied on trade between UK and EU.
- Which of the above statements is/are correct?
- (a) Only 2 (b) 2 and 3
(c) 1 and 2 (d) Only 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

- प्र. पोस्ट ब्रेक्जिट डील के तहत हुए समझौते पर प्रकाश डालते हुए इस समझौते से भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए? (250 शब्द)
- Q. While highlighting the agreement made under the Post Brexit Deal, discuss the possible effects of this agreement on India? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।